

प्रेषक,

संतोष बड़ोनी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 16 नवम्बर, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत आदि कार्यो हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से अतिरिक्त धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1043/तेरह-07(आ0प्र0)/2010-11, दिनांक 28.10.2014 तथा आदेश संख्या-1119/तेरह/दै0आ0, दिनांक 28.08.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2010-11 में अतिवृष्टि के कारण शहर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने के दृष्टिगत क्षतिग्रस्त सार्वजनिक विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत आदि के कुल 127 कार्ययोजनाओं हेतु कुल लागत ₹ 1055.21 लाख के सापेक्ष कुल ₹ 450.00 लाख की स्वीकृति प्रथम किस्त के रूप में राज्य आपदा मोचन निधि व राष्ट्रीय आकस्मिकता कोष (NCCF) से की गयी है, अवशेष कार्यो के भुगतान हेतु धनावंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक/विभागीय परिसम्पत्तियों की तात्कालिकता के दृष्टिगत मरम्मत आदि कार्य हेतु आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 127 कार्ययोजनाओं की कुल लागत ₹ 1055.21 लाख में से उपलब्ध करायी गयी सूची के क्रमांक-28, 120, 122 को छोड़कर शेष 124 कार्ययोजनाओं के सापेक्ष ₹ 450.00 लाख (₹ चार करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्थाओं को पूर्व में किया जा चुका है। उक्त कार्यो के सम्बन्ध में शासन द्वारा गठित जांच समिति द्वारा जांचोपरान्त तत्पश्चात शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त उक्तानुसार पूर्व में पूर्ण कराये गये कार्यो में से अवशेष बचे कार्यो के भुगतान हेतु ₹ 597.56 लाख (₹ पांच करोड़ सतानब्बे लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. आगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग के अधिशासी अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली गई हो।
2. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन किया गया हो।
3. आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी एवं निर्माण ईकाई का होगा।



4. स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त है तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है।
5. जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट अथवा इस बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप से पुष्टि हो जाय।
6. कार्य की गुणवत्ता के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी/निर्माण एजेन्सी/सम्बन्धित विभागाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. भारत सरकार द्वारा एक स्वतंत्र एजेन्सी से भी कार्यों का निरीक्षण व मूल्यांकन किया जाता है। अतः जनपद स्तर पर गठित टीम द्वारा कार्य की क्षति, धनराशि के सही उपयोग गुणवत्ता आदि की समीक्षा कर लिया जाना आवश्यकीय होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2016 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यकीय होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाय और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दी जाय।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्यय अनुदान संख्या-6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-00-13-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ. शा. संख्या-150NP/XXVII-5/2015, दिनांक 16 नवम्बर, 2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संतोष बड़ोनी)
उप सचिव

संख्या-3874 (1)/XVIII-(2)/15-4(16)/2011 एवं तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- कोषाधिकारी, हरिद्वार।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7- बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
- 8- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संतोष बड़ोनी)
उप सचिव